



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राप्तिकार में प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

व. 50]

No. 50]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 31, 1992/माघ 11, 1913  
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 31, 1992/MAGHA 11, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

मानव जनरेशन विकास मन्त्रालय

(महिला और बाल विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1992

मा. का. नि. 74(अ):—केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 (1990 का 20) को धारा 4 की उपधारा (5) के साथ पठित धारा 17 द्वारा प्रवत्त विधियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को मरेय बेतन और भत्तों तथा सेवा के अन्य निवन्धन और शर्तों का विनियमित करने के लिए निम्न-लिखित नियम बनाते हैं, अबतः—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ग्रान्ट्रीय महिला आयोग (अध्यक्ष और सदस्य बेतन तथा भत्ते और अन्य सेवा जर्ते) नियम, 1992 है।

(2) ये ग्रान्ट्रीय में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिमाया:—इन नियमों में, जब तक कि मंदर्भ से अन्यथा घोषित न दी—

(क) “अधिनियम” से ग्रान्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 (1990 का 20) अधिप्रेत है,

(ख) “अध्यक्ष” से आयोग का अध्यक्ष अधिप्रेत है।

3. बेतन और भत्ते:—(1) ये नियम (2) में अन्यथा यथा उप-बंधित के सिवाय, अध्यक्ष को प्राठ हजार रु. प्रति मास बेतन और प्रत्येक सदस्य को सात हजार छह सौ रु. प्रति माह बेतन दिया जाएगा;

परन्तु यह कि जहाँ अध्यक्ष अथवा सदस्य संघ राज्य क्षेत्र प्रणालीन, अद्विसरकारी निकायों, प्रैलिक सेक्टर उपकरण, भाव्यता प्राप्त प्रनुसंधान संस्था में सेवानिवृत्त कोई सरकारी अधिकारी या पदधारी है तो उसे पेंशन या सेवापांक फायदों के पेंशनी मूल्य या दोनों सहित सदेय बेतन, अध्यक्ष को दणा में प्राठ हजार रुपए प्रतिमास और सदस्य की दणा में सात हजार रु. भी रुपए प्रतिमास से अधिक नहीं होगा।

(2) यदि अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य केन्द्रीय सरकार अथवा किसी ग्रान्ट्रीय सरकार की सेवा में है तो उसका बेतन उसे लागू नियमों के प्रनुसार विनियमित किया जाएगा।

4. महंगाई भत्ता:—प्रध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य केन्द्रीय सरकार के समूचित स्तर के अधिकारियों को अनुज्ञेय दरों पर अपने वेतन के अनुरूप महंगाई भत्ता प्राप्त करेंगे।

5. नगर प्रतिपूति भत्ता:—प्रध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, केन्द्रीय सरकार के समूचित स्तर के अधिकारियों को अनुज्ञेय दरों पर अपने वेतन के अनुरूप नगर प्रतिपूति भत्ता प्राप्त करेंगे।

6. पदावधि:—(1) अधिनियम को धारा 3 को उपर्याहा (2) में विनिर्दिष्ट प्रबन्ध के निम्न व्याप्ति को, जिसको आयु पैसठ वर्ष की न हो ही हो, प्रध्यक्ष अवधा सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा।

(2) प्रध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, जब तक कि उपर्याहम को धारा 4 को उपर्याहा (3) के अन्तर्गत कार्यकाल पूरा होने से पूर्व हटा नहीं दिया जाता, तो उन वर्ष से अन्तिक प्रवृत्ति तक प्रध्यक्ष 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, उनमें से जो भी पहले हो, आवास पद प्राप्त करेगा।

(3) उपर्याहम (1) में किना आने के होने पुरा भा कुछ भी विवेदों के आवश्यक—

(क) कोई व्यक्ति, जिसने अधाक का पद धारण किया है, का पुनः नामनिर्देशन किया जा गकेगा, और

(ख) कोई व्यक्ति, जिसने सदस्य का पद धारण किया है, गदस्य को रूप में पुनः नामनिर्देशन किए जाने या प्रध्यक्ष के रूप में नामनिर्देशित किए जाने का पात्र होगा।

परन्तु यह भी कि सदस्य सचिव को छोड़ कोई व्यक्ति, जिसने सदस्य या प्रध्यक्ष किनी भी रूप में दो कार्यादिविधियों के लिए पद धारण किया है, प्रध्यक्ष अवधा सदस्य के रूप में पुनः नामनिर्देशित किए जाने का पात्र नहीं होगा।

(4) यदि व्यक्ति या अन्य प्रसंपर्यों ने प्रध्यक्ष अवधा कार्य करने में अधीक्षित भी रूप में दो कार्यादिविधियों के लिए सदस्य को प्रध्यक्ष के रूप में कार्य करना के लिए नामनिर्देशन करेगा और हम प्रकार नामनिर्देशित सदस्य प्रध्यक्ष के लिए से कार्यभार संभालने तक प्रध्यक्ष का पद धारण करेगा।

(5) यदि मृत्यु हो जाने से यात्रणा पत्र देने से अधिक का पर रिक्त होता है तो केन्द्रीय सरकार किसी अन्य सदस्य को प्रध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्देशित करेगी और हम प्रकार नामनिर्देशित सदस्य, प्रध्यक्ष का रिक्त पद प्रध्यनियम की धारा 1 के उपर्याहा (4) के अधीन नए नामनिर्देशन से भरे जाने तक, प्रध्यक्ष का पद धारण करेगा।

7. छुट्टी:—प्रध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य निमानुसार छुट्टियों का हकदार होगा,—

(क) समय-समय पर यथा भौतिकित केन्द्रीय मिशन सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अनुसार अर्जित अवकाश, अर्द्धवेळ अवकाश और परिवर्तित अवकाश,

(ख) समय-समय पर यथा भौतिकित केन्द्रीय मिशन सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अन्तर्गत अस्थाई सरकार कर्मचारियों को यथा अनुज्ञेय अमाधारण छुट्टी।

8. छुट्टी मनूर करने के लिए प्रधिकारी—किसी सदस्य की छुट्टी मनूर करने के लिए प्रध्यक्ष सदस्य प्रधिकारी होंगा और प्रध्यक्ष की छुट्टी मनूर करने ले लिए केन्द्रीय सरकार सदस्य प्राधिकरण होगी।

9. यात्रा भत्ता:—(1) प्रध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य केन्द्रीय सरकार के श्रेणी "क" अधिकारियों को अनुज्ञेय अपने वेतन के अनुरूप दरों पर यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(2) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य यात्रा भत्तों और दैनिक भत्तों से गंतव्यित अपने विलों के माध्यमों में स्वयं नियन्त्रित अधिकारी होंगे।

10. आवास सुविधा:—(1) प्रध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य उस प्रवाह का सरकारी आवास प्राप्त करने के हकदार होंगे जैसा कि भारत सरकार द्वारा निर्वाचित किया जाए।

(2) यदि प्रध्यक्ष अवधा किसी सदस्य को उप नियम (1) में उल्लिखित आवास नहीं दिया जाता या वे स्वयं उपभोग नहीं करते हैं तो उन्हें केन्द्रीय सरकार में वसुचित रैक के अधिकारियों को अनुज्ञेय दरों पर प्रत्येक माह गकान किया जाए।

11. आहत सुविधा:—प्रध्यक्ष और प्रत्येक गवर्नर भारत सरकार के स्टाफ कार नियमों के अनुसार सरकारी और निजी कार के लिए यात्रा करने से लेते स्टाफ कार की सुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे।

12. चिकिता उपचार सुविधा:—प्रध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य चिकिता उपचार और हाँस्प्रिट्स सुविधा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, जैसा कि केन्द्रीय सरकार के अंशदायी स्थानस्थ सेवा योजना नियम, 1965 में उपचित विधा गया है जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किया जाए।

13. पेणन:—(1) प्रध्यक्ष या सदस्य जो अपनी नियुक्ति के समय केन्द्रीय अवधा किसी राज्य सरकार की सेवा में था, नियुक्ति का तारीख से 6 माह के अन्दर अपना विकल्प देने पर, यसाम्यति, प्रध्यक्ष या सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति की तारीख से उन नियमों के अंतर्गत पेणन तथा प्रत्येक सेवा तिवृति यात्रा प्राप्त करने का अधिकारी होंगा जो उग्र गेवा को लागू दें जिसका वह था।

परन्तु ऐसी परिस्थिति में, प्रध्यक्ष अवधा सदस्य के रूप में उतका वेतन सकल पेणन की रकम के बाबत कब तक दिया जाएगा जिसमें पेणन का एक भी भाग जिसे संपर्कित किया गया हो और अन्य सेवा तिवृति स्थानों के बाबत पेणन शामिल है तथा वह अपनी पेणन और अन्य सेवा तिवृति आम प्रलग से प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) यदि प्रध्यक्ष अवधा कोई सदस्य जो अपनी उक्त नियुक्ति के समय केन्द्रीय अवधा राज्य सरकार की सेवा में था और उप नियम (1) में नियन्त्रित विकल्प नहीं छुना तो वह सदस्य के रूप में अपनी सेवा को लागू नियमों के अधीन पेणन तथा सेवा नियुक्ति लाभ के लिए जोड़ सकेगा जिसमें वह इस नियुक्ति से योग्य पहले था।

(3) प्रध्यक्ष अवधा ऐसे सरकार कोई पेणन संप्रेष नहीं होगी जो प्रध्यक्ष अवधा सदस्य को पद प्राप्त करने से ठीक पहले केन्द्रीय अवधा राज्य सरकार की किसी सेवा में नहीं था।

14. भविष्य निधि:—(1) प्रध्यक्ष अवधा कोई सदस्य, जो आयोग में अपनी नियुक्ति के समय केन्द्रीय सरकार अवधा विनी राज्य सरकार की सेवा में था तथा जिसे सामान्य भविष्य निधि अवधा अंशदायी भविष्य निधि के कायदों में सम्मिलित किया गया था, अपनी सेवा में लागू नियमों के अनुसार अवधा राज्य सरकार की किसी सेवा में नहीं था।

नियुक्ति की ओर से उस नियिति में सदैय अंगदान, आयोग में अध्यक्ष अथवा मदस्य की नियुक्ति की तारीख से अध्यक्ष अथवा मदस्य के स्थान में उसकी नियुक्ति के कार्यकाल के दौरान शायां द्वारा सदैय होगा।

स्पष्टीकरण 1:—इस उत्तरमें विकल्प अनुने वाला कोई भी मदस्य, ऐसे मदस्य के स्थान में आयोग कार्यकाल के दौरान राज्यपति को अपना विकल्प नियुक्त रखा राज्यपति करेगा जो इस प्रकार प्रत्येक नियुक्ति द्वारा दिया विकल्प अन्तिम होगा।

स्पष्टीकरण 2:—यदि कोई मदस्य अपने विकल्प का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय अथवा रियो राज्य सरकार के अंतर्गत सेवा से नियुक्ति पर अंगदायी भविष्य नियिति के लाल आपने कर लेता है तो इन नियमों के प्रत्येक वह नव वेतन प्राप्त करने का पाव नहीं होगा अब तक कि उस भविष्य नियिति में सरकारी अंगदान की राशि व्याज महिला एकाउंट और साथ में अन्य सेवानिवृत्ति नाम, यदि कोई हो, सरकार को नहीं लौटा देता।

(2) ऐसे मदस्य के स्थान में अपनी नियुक्ति के समय अध्यक्ष अथवा कोई मदस्य जो,

(i) केन्द्रीय सरकार अथवा रियो राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय निकाय प्रत्यवा पूर्ण स्वयं से या आंशिक स्वयं से सरकारी अथवा सरकार के नियंत्रणाधीन किसी अन्य प्राधिकरण की सेवा में था और उसने ऐसी नियुक्ति से पूर्व उस सेवा को लागू नियमों के अंतर्गत जिमका वहां आयोग प्रत्येक पेशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाल लेते का विकल्प छुनता है/चुना हो, या

(ii) केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय निकाय प्रत्यवा पूर्ण स्वयं से या आंशिक स्वयं से सरकारी अथवा सरकार के नियंत्रणाधीन किसी अन्य प्राधिकरण के अंतर्गत सेवा ते लेवृत हो चुना हो और जो/जिसने इन नियमों के अंतर्गत पेशन योजना के अंतर्गत शार्टिन होने का विकल्प नहीं चुनता/न चुना हो या

(iii) केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय निकाय प्रत्यवा पूर्ण स्वयं से या अथवा सरकारी अथवा सरकार के नियंत्रणाधीन किसी अन्य प्राधिकरण की सेवा में नहीं था, और इन नियमों के अंतर्गत पेशन लाल आप प्राप्त करने का हकदार नहीं दल पाना अथवा इन नियमों के अंतर्गत पेशन योजना में शामिल होने था विल्लय नहीं चुनता।

वह अंगदायी भविष्य नियिति योजना के फायदों में सम्मिलित किए जाने का हकदार होगा और इस प्रयोजन के लिए वह समय-समय पर यथा संशोधित अंगदायी भविष्य नियिति (भारत) नियम, 1962 द्वारा प्राप्त होगा।

15 अवणिट उपबंध:—अध्यक्ष तथा मदस्यों के सेवाशर्ते जिनके लिए इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, वे हींसी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवशायित की जाएँ।

[म. 9-61/90-राज्य. बन्ध.]  
उमा पिल्लै, समूक संचय।

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE  
DEVELOPMENT  
(Department of Women and Child Development)  
NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 1992

G.S.R. 74(E).—In exercise of the powers conferred by Sec. 17 read with sub-section (5) of section

4 of the National Commission for Women Act, 1990 (20 of 1990), the Central Government hereby makes the following rules regulating the salaries and allowances payable to and other terms and conditions of service of the Chairperson and Members of the National Commission for Women, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Commission for Women (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 1992.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the National Commission for Women, Act, 1990 (20 of 1990);

(b) "Chairperson" means the Chairperson of the Commission.

3. Salaries and allowances.—(1) Save as otherwise provided in sub-rule (2), the Chairperson shall be paid a salary of rupees eight thousand per month and every Member shall be paid a salary of rupees seven thousand and six hundred per month :

Provided that where the Chairperson or a Member is a retired Government Officer or official from Union Territory Administration, Semi-Government bodies, public sector undertaking, recognised research institution, the salary payable together with the pension or pensionary value of the terminal benefits, or both, received by him shall not exceed in the case of Chairperson rupees eight thousand per month and in the case of a Member rupees seven thousand and six hundred per month.

(2) If the Chairperson or a Member is in service of the Central or a State Government, his salary shall be regulated in accordance with the rules applicable to him.

4. Dearness allowance.—The Chairperson and every Member shall receive dearness allowance appropriate to their pay at the rates admissible to officers of the appropriate level of the Central Government.

5. City compensatory allowance.—The Chairperson and every Member shall receive city compensatory allowance appropriate to their pay at the rates admissible to officers of the appropriate level of the Central Government.

6. Tenure of office.—(1) Any person falling within the categories specified in sub-section (2) of section 3 of the Act and who has not attained the age of sixty-five years may be nominated as the Chairperson or as a Member.

(2) The Chairperson and every Member shall, unless removed from office under sub-section (3) of section 4 of the Act, hold office for a period not exceeding three years, or till the age of sixty-five years, whichever is earlier.

(3) Notwithstanding any thing contained in sub-rule (1),

- (a) A person who has held the office of Chairperson shall be eligible for re-nomination, and
- (b) a person who has held the office of a Member shall be eligible for re-nomination as a Member or nomination as a Chairperson:

Provided that a person who has held office for two terms, in any capacity except the Member-Secretary, shall not be eligible for re-nomination as Chairperson or as Member.

(4) If the Chairperson is unable to discharge his functions owing to illness or other incapacity, the Central Government shall nominate any other Member to act as Chairperson and the Member so nominated shall hold office of Chairperson until the Chairperson resumes office.

(5) If a vacancy occurs in the office of the Chairperson by reason of his death or resignation, the Central Government shall nominate any other Member to act as Chairperson and the Member so nominated shall hold office of Chairperson until the vacancy is filled by a fresh nomination under sub-section (4) of section 4 of the Act.

7. Leave.—The Chairperson and every Member shall be entitled to leave as follows :—

- (a) earned leave, half pay leave and commuted leave in accordance with the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, as amended from time to time.
- (b) extra-ordinary leave as admissible to the temporary Government servants under the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 as amended from time to time.

8. Leave sanctioning authority.—The Chairperson shall be the authority to sanction leave to a Member and the Central Government shall be the authority competent to sanction leave to the Chairperson.

9. Travelling Allowance.—(1) Chairperson and every member shall be entitled to draw travelling allowances and daily allowance at the rates appropriate to their pay admissible to Group A officers of the Central Government.

(2) The Chairperson and every Member shall be his own controlling officer in respect of his bills relating to travelling allowances and daily allowances.

10. Residential accommodation.—(1) The Chairperson and every member shall be entitled to the use of an official residence as may be determined by the Government of India.

(2) If the Chairperson or a Member is not provided with or does not avail himself of the accommodation specified in sub-rule (1), he shall be paid every month house rent allowance at the rates admissible to officers of an appropriate rank in the Central Government.

11. Facility for conveyance.—The Chairperson and every member shall be entitled to the facilities of staff car for journeys for official and private purpose in accordance with the Staff Car Rules of the Government of India.

12. Facility for medical treatment.—The Chairperson and every Member shall be entitled to medical treatment and hospital facilities as provided in the Central Government Contributory Health Scheme Rules, 1954 or as may be determined by the Central Government.

13. Pension.—(1) The Chairperson or a Member who, at the time of his appointment as such was in the service of the Central or State Government, shall, at his option to be exercised within a period of six months from the date of his appointment be entitled to draw his pension and other retirement benefits the rules applicable to the service to which he belonged with effect from the date of his appointment as Chairperson or Member, as the case may be :

Provided that, in such an event, his pay as Chairperson or Member shall be reduced by an amount equivalent to the gross pension including any portion of the pension which may have been commuted and the pension equivalent of other retirement benefits and he shall be entitled to draw his pension and other retirement benefits separately.

(2) The Chairperson or a Member, who at the time of his appointment as such, was in the service of the Central or State Government, if he does not exercise the option specified in sub-rule (1) shall count his service as Member for pension and retirement benefits under the rules applicable to the service to which he belonged immediately before such appointment.

(3) No pension shall be payable to the Chairperson or a Member who, immediately before assuming office as the Chairperson or a Member, was not in any service of the Central or State Government.

14. Provident Fund.—(1) The Chairperson or a Member who at the date of his appointment to the Commission was in the service of the Central or State Government and who had been admitted to the benefits of General Provident Fund or Contributory Provident Fund, may continue to subscribe to that Fund until the date on which he retires according to rules applicable to him in his service. In the case of the Contributory Provident Fund, the employers' contribution payable to that Fund shall as from the date of the Chairperson or Member's appointment to the Commission be payable by the Commission during the tenure of appointment as such Chairperson or Member.

Explanation I.—A Member exercising his option under this sub-rule shall communicate his option in writing to the President during his tenure as such Member and the option so exercised shall be final.

Explanation II.—If a Member exercising his option has received any benefits of Contributory Provident Fund on retirement from service under the Central or State Government, he shall not become eligible for pension under these rules unless he receives in lump sum the Government contribution to that Provident Fund with interest thereon together with other retirement benefits, if any.

(2) The Chairperson or a Member who at the time of his appointment as such member—

- (i) was in the service of the Central or State Government or of a local body, or any other authority wholly or substantially owned or controlled by Government and who opts, or had opted, to draw his pension and other retirement benefits under the rules applicable to the service to which he belonged prior to such appointment, or
- (ii) had retired from service under the Central or State Government, a local body or other authority wholly or substantially owned or

controlled by Government and who does not opt, or had not opted, to come under the pension scheme under these rules, or

- (iii) was not in the service of the Central or State Government, a local body or any other authority wholly or substantially owned by Government and either does not become entitled to any pensionary benefits under these rules or opts not to come under the pension scheme under these rules, shall be entitled to be admitted to the benefit of the Contributory Provident Fund Scheme and for this purpose shall be governed by the Contributory Provident Fund (India) rules, 1962 as amended from time to time.

15. Residuary provision.—The conditions of service of the Chairperson and the Members for which no express provision has been made in these rules shall be as determined by the Central Government.

[No. F. 9-61/90-WW]  
UMA PILLAI, Lt. Secy.

